respect of cigarettes, petroleum products, electricity, man-made fabrics, man-made fibres and yarn, non-celulosic spun yarn, iron and steel products, electric wires and cables and motor vehicles. The reasons for the shortfall vary, but in broad terms, these can be discribed as lower clearances during this period, court cases and other disputes and also arrears of duty. The shortfall in customs revenue is largely in the case of chemicals, iron and steel, man-made fibres and filament tow. Here again the reasons are fall in commodity prices abroad, and court cases and tax disputes. The Government is keeping a close watch on the trend of revenue collections for appropriate action including legislative.

Action against Black Marketeers and Hoarders of Essential Commodities

3207. SHRI JAI NARAIN ROAT: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the number of blackmarketeers and hoarders of essential commodities such as foodgrains, sugar and edible oil etc. apprehended in each State during 1981 and till date;

(b) the details of the items seized and the value thereof; and

(a) the number of black marketeers the persons so apprehended and what stringent measures have been taken or are proposed to be taken by Government to stop such anti-social activities?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF): (a) and (b). A statement showing the number of black-marketeers and hoarders of essential commodities, apprehended as per information received from 22 State Governments/Union Territories during 1981, is laid on the table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—5563/82] alongwith details of the items seized and value thereof.

The information in respect of 9 other State Governments/Union Territories alongwith the same information till date during 1982 is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) As per reports received from these States/Union Territories, appropriate action was taken against such persons under the Essential Commodities Act, 1955 and the Orders issued thereunder. The penal provisions of the Essential Commodities Act, 1955 have recently been made more stringent with the enactment of the Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981 which has been brought into effect with effect from 1-9-1982. This is expected to be more deterrent to the black-marketeers and hoarders of essential commodities.

लनकरनसर, बीकानेर में चांदमारी क्षेत्र

3208. श्री मनूफल सिंह चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चांदमारी क्षेत्र बसाने के उद्देश्य से बीकानेर जिले की लनकरनसर तहसील के 34 गांवों को खाली करा रही है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब इस चांदमारी क्षेत्र में गोली चलाने का अभ्यास शुरु होता है तो किसानों को अपने खेतों में नहीं जाने दिया जाता है और पशु रुके रहते हैं ;

(ग) क्या इन 34 गांवों का क्षेत्र असिंचित है तथा हर वर्ष वे अकाल से प्रभावित होते हैं ;

(घ) क्या इन गांवों में अकाल राहत कार्य बन्द कर दिया गया है ;

(ङ) क्या सरकार को यह पता है कि यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है तथा पशुधन का केन्द्र है और दिल्ली की दुग्ध डेयरियों को अधिकांश सप्लाई इन गांवों से होती है ; और

(च) क्या सरकार का विचार इन 34 गांवों को अलग छोड़ देने और चांदमारी क्षेत्र की स्थापना किसी अन्य खाली क्षेत्र में कराने का है?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मेनोयवर्स, फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस अधिनियम 1938 जिसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाता है, के अन्तर्गत अधिसूचित रेंज इस क्षेत्र में 1975 से लागू है। सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव कुछ अतिरिक्त क्षेत्र सहित इस क्षेत्र को अर्जित करने का है। फील्ड फायरिंग के दौरान इस क्षेत्र के खतरनाक जोन में जान की जो क्षति होगी तथा मनुष्यों और पशुओं को जो हानि पहुंचेगी उसके जोखिम को देखते हुए इनको इस क्षेत्र से खाली कराना होगा। इसी प्रकार इन्हें वास्तविक फायरिंग के दौरान इस खतरनाक जोन में जाने से रोका जाता है। प्रभावित व्यक्तियों के सामान्य जीवन में इससे जो अव्यवस्था पैदा हो जाती है उसके बदले उन्हें पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाता है।

2. जिस सामान्य क्षेत्र को अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव है वह सूखाग्रस्त क्षेत्र है जिस में किसी प्रकार की सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। इस क्षेत्र में आबादी बहुत कम है और यहां बालू के टीलों से भरा हुआ है। इस क्षेत्र के ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। जिस क्षेत्र को अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव है उसी की सीमाएं राजस्थान सरकार के साथ परामर्श कर के निर्धारित की जा रही हैं जिस से यहां के स्थानीय निवासियों को कम से कम हटाना पड़े। चूंकि इस समय कोई ऐसा अन्य उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं है जिस में इस प्रस्ताव के बनाये स्थानीय लोगों को कम कठिनाईयां उठानी पड़े। इस लिए इसके लिए वैकल्पिक स्थलों का पता लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले 5–6 वर्षों के दौरान कई स्थलों के सुझाव दिए गए थे और इन सभी पर राज्य सरकार और थल सेना प्राधिकारियों की परामर्श से सावधानी पूर्वक विचार किया गया परन्तु इस उद्देश्य के लिए किसी भी स्थल को उपयुक्त नहीं पाया गया है।

Clubbing of Income of Spouses

3209. SHRIMATI SANYOGITA RANE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that clubbing the incomes of spouses under Income-tax Law compels women to pay tax at a higher slab;

(b) whether Government are aware that these provisions make discrimination and deny women equality; and

(c) whether Government propose examining the existing provisions and restore women the right to a free slab of income?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO): (a) and (b). A note explaining the relevant provisions of the Income-tax Act, 1961 and their constitutional validity is laid on the table of the floor. [*Placed in Library. See* No. LT—5564/82].

(c) In view of the position as set out in the note, this question does not arise.

Inscribing the world "Seconds" on cloth

3210. DR. A. U. AZMI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the mill-made cloth does not show metre-wise